राष्ट्रीय यूपी के अगले चुनाव के लिए अभी से तय हो रहा एजेंडा

यूसुफ किरमानी

बात थोड़ा लंबी है...इस बात के कई आयाम हैं। फिर भी बताता हूँ।

ये कथित सिस्टम फेल होने और पाँच राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद की बात है।

देश के कुछ जाने-माने पत्रकारों और प्रभावशाली लोगों (Influencer) ने एक नया नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है। इसका ख़ास मक़सद है और वो मक़सद अगले यूपी चुनाव से जुड़ा है।

एनडीटीवी ग्रुप का एक लोकप्रिय पत्रकार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को अदालत के कटघरे में बुलाकर सवाल करने की मांग कर रहा है। वह पत्रकार प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने या उनका इस्तीफा नहीं मांग रहा है।

जाने-माने पत्रकार शेखर गुप्ता कह रहे हैं कि टीम लीडर यानी प्रधानमंत्री मोदी को टीम बदल लेनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक नियम ये है कि कोई भी टीम नेता से होती है। नेता बदलो, टीम तो बदल ही जाएगी।

ऐडमैन और Influencer सुहेल सेठ कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को स्वास्थ्य मंत्रालय का भी चार्ज दिया जाना चाहिए। सुहेल सेठ के पास प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने के लिए सवाल नहीं है।

इनके अलावा भी ढेरों ढिंढोरची हैं। हाल ही में चमके कुछ बड़े यूट्यूबर भी इस नैरेटिव को गढ़ने की मुहिम में शामिल हैं। इनमें से कोई भी पंचायत चुनाव में भाजपा की हार और सपा की जीत पर बात नहीं कर रहा है।

...और इसी बीच अचानक अदालत भी

सक्रिय हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के हाई कोर्ट सरकार से सवाल करने लगते हैं। अदालत की टिप्पणियां सुनें तो लगेगा कि बस अभी वो किसी मंत्री को फांसी की सजा सुना देगी। ...अदालतें, दरअसल सरकार का सेफ्टी वॉल्व हैं। अदालतें जनता का गुस्सा शांत करने के लिए ही सक्रिय होती हैं। आप उम्मीद पाल लेते हैं कि अब तो अदालत ने सरकार को उधेड़ दिया है। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह छलावा है। इस देश में अदालतों का कथित गुस्सा, कड़ी टिप्पणी भी अब कड़ी निन्दा जैसी हो गई है। दिल्ली का बत्रा अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, गुड़गांव का कीर्ति अस्पताल, लखनऊ, बेंगलुरु और चेन्नै के अस्पतालों में हुई मरीजों की मौत के लिए कोई जवाबदेही तय हुई। किसी अदालत ने इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही। अदालत की टिप्पणियां बस आपका गुस्सा शांत कर रही हैं। और कुछ नहीं। वापस अपनी मूल बात पर लौटते हैं।

...तो नैरेटिव गढ़ने वाले पत्रकार और प्रभावशाली लोग लेखिका और एक्टिविस्ट अरूंधति रॉय की तरह यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी, बस हुआ, अब कुर्सी छोड़िए। वे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की तरह जनता से विद्रोह करने का आह्वान तक नहीं कर पा रहे हैं।

ये नेरेटिव ऐसे वक्त में सामने आया है, जब देश के सामने मोदी का तिलिस्म टूट चुका है। सारे पत्ते खुल चुके हैं। मोदी की छवि तार-तार हो चुकी है। अरूंधति रॉय और पी. चिदंबरम जैसी बात कहने की हिम्मत आज किसी बड़े भारतीय पत्रकार में नहीं है। तो इस नैरेटिव सेट करने के पीछे मक़सद क्या है? मक़सद ये है कि इस हंगामे से किसी तरह मोदी को निकाल कर कुछ नए मंत्रियों के साथ मोदी को नए रंगरूप में पेश करना। दरअसल, अगले साल यूपी विधानसभा का चुनाव है। असली रण वहीं होना है। इस नैरेटिव का सीधा संबंध यूपी चुनाव से है।

अगर यूपी हाथ से निकला तो फिर भाजपा के लिए केंद्र में शासन करना तक मुश्किल हो जाएगा। उसके नेता सार्वजनिक रूप से कहीं आ-जा नहीं सकेंगे। इसलिए मोदी के वॉर रूम में न सिर्फ़ इस नेरेटिव को गढ़ने के लिए हरकारे लगा दिए गए हैं बल्कि यूपी को किसी भी क़ीमत पर फ़तह करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में यूपी की फ़िज़ा में ज़हर ही ज़हर घुलता हुआ दिखे तो ताज्जुब मत कीजिएगा। अब मोदी के तरकश का हर तीर यूपी के लिए है।

यही वजह है कि बंगाल में चुनाव ख़त्म होते ही हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, उसे पूरी तरह भुनाया गया। बंगाल की हिंसा में सिर्फ़ भाजपा ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और सीपीएम के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। उनके दफ़्तर जलाए गए हैं। लेकिन हमें मीडिया बता रहा है कि टीएमसी हिंसा कर रही है, और उसमें भी साम्प्रदायिक एंगल देते हुए टीएमसी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार बताया गया है। टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं को किसने मारा, मीडिया में इस सवाल का जवाब गायब है। टीएमसी और सीपीएम के दफ्तर जलाए गए, किसने जलाए, जवाब नहीं आएगा।

बंगाल की हिंसा के विरोध में 5 मई को जिस तरह भाजपा ने अपने कैडर से धरना दिलवाया, उसमें भड़काने वाले बयान दिए गए। वह बताता है कि बंगाल हिंसा की आड़ में एक तरफ़ वो मोदी की तमाम नाकामी से ध्यान हटाना चाहती है। दूसरी तरफ़ वो यूपी के मद्देनज़र अपना हिन्दू मुसलमान कार्ड खेलना जारी रखना चाहती है।

स्पष्ट है कि पाँच राज्यों के नतीजे आने के बाद मोदी का वॉर रूम फिर से यूपी को लेकर चुनावी मोड में आ चुका है। कोरोना की रफ़्तार कम होते ही मोदी के वाराणसी दौरे से इसकी शुरुआत होगी। वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर - ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उनका इशारों में बयान आयेगा और जिस पिच पर भाजपा खेलती है, उसके टर्फ़ को और मज़बूत किया जाएगा। यहीं से तय होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) उनकी पिच पर खेलेंगे या नहीं? मोदी और भाजपा के तमाम हरकारे तैयार बैठे हैं। वे कांग्रेस और सपा को भाजपा की पिच पर ही खेलने को मजबूर करेंगे। भाजपा ने अभी हाल ही में पूरे यूपी के चुनिंदा शहरों में मीडिया को लेकर काफ़ी पैसा निवेश किया है। छोटे-छोटे अख़बारों तक में भाजपा के विज्ञापन छपेंगे। सैकड़ों यूट्यूबर तैयार किए गए हैं।

मोदी के वॉर रूम में कांग्रेस और सपा के ऐसे नेताओं की सूची बन चुकी है, जो ज़हरीले बयानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे बयानों पर ताली बजाने वाले तमाम मुसलमान खुद हिन्दू ध्रुवीकरण की रसद मुहैया कराएँगे। मुसलमानों का राष्ट्रीय नेता बनने की ओवैसी साहब की हसरत बिना यूपी चुनाव लड़े बिना पूरी नहीं होगी, तो वो भी बड़ा दांव लगाने के लिए बेक़रार हैं।

इस तरह आपने देख और समझ लिया कि नैरेटिव को भाजपा की फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। फिर उसे तमाम पत्रकार, प्रभावशाली लोग, चैनल वाले, अन्य राजनीतिक दलों के नेता जाने-अनजाने फैलाते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि कुछ पत्रकार और लेखकों की छवि ऐसी गढ़ी गई है कि वे नजर तो आएंगे मोदी विरोध में लेकिन दरअसल वे सभी अपने तरीके से मोदी, भाजपा, आरएसएस के एजेंडे को ही बढ़ा रहे होते हैं।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)

बंगाल की हिंसा एकतरफ़ा नहीं, गोदी मीडिया कर रहा है बदमाशी

कृष्णकांत

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मामला इतना सीधा नहीं है। सोशल मीडिया और कुछ खबरों को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि तृणमूल के लोग बीजेपी के लोगों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष है।

चुनाव नतीजे के बाद राज्य में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक, बीजेपी ने दावा किया है कि उनके छह कार्यकर्ता मारे गए। पुलिस ने 12 मौतों की पुष्टि की लेकिन यह नहीं बताया है कि मृतक किस पार्टी से जुड़े थे।

मीडिया ये खबर चला रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं, लेकिन वह ये नहीं पूछ रहा है कि मारे गए 12 लोगों में छह बीजेपी के हैं तो बाकी छह कार्यकर्ता किसके हैं? उन्हें किसने मारा? क्या बीजेपी भी इस हिंसा में बराबर की भागीदार नहीं है?

भाषा की खबर के मुताबिक, बर्धमान में मारे गए चार लोगों में तीन तृणमूल के हैं और एक बीजेपी का। इस बारे में पूछने पर बीजेपी ने कहा कि ये 'लोगों की प्रतिक्रिया' का नतीजा है। हुगली में भी एक तृणमूल कार्यकर्ता मारा गया और तीन घायल हैं।

जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के बयान को ही अंतिम सच मानकर बहस की जा रही है। इन्हीं नेताओं के बयान को हेडिंग बना दिया जा रहा है। अगर जेपी नड्डा का दावा सच है तो ममता बनर्जी का दावा सच क्यों नहीं है? इन दोनों में से जो भी दोषी है, क्या वह मीडिया को बताएगा कि वह हिंसा कर रहा है?

मीडिया न तो खुद खोजबीन कर रहा है, न किसी से सवाल पूछ रहा है, न अपने से कोई स्वतंत्र रूप से कोई दावा करने की स्थिति में है। ये सच है कि तृणमूल चुनाव जीती है और इस हिंसा के लिए उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया बीजेपी के आरोप को ही अंतिम सच मानकर रिपोर्ट कर रहा है।

आरोप दोनों लगा रहे हैं तो दोनों से सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? ये सब जानते हैं कि टीएमसी हिंसा का सहारा लेती है। उससे पहले वामपंथियों पर हिंसा का आरोप लगता था और उनकी हिंसा को टीएमसी की हिंसा ने मात दे दी। अब बीजेपी अपनी हिंसा से टीएमसी की हिंसा को जीतना चाहती है। बंगाल की राजनीति में हिंसा सबसे कारगर हथियार है और टीएमसी की तरह बीजेपी भी उसी हथियार पर अपना हाथ साफ कर रही है।

बाकी हिंसा और दंगा के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड जगजाहिर है। पिछले साल दिल्ली जनसंहार (Delhi Genocide 2020) में क्या हुआ था, ये दुनिया देख चुकी है।

मुझे तो यह कोरोना की विभीषिका से ध्यान हटाने की साजिश लगती है ताकि लोग हिंसा और हत्या में उलझे रहें, ये कोई न पूछे कि साल भर में आक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगे?

बंगाल में भाजपा का ध्रुवीकरण फ़ॉर्मूला क्यों हुआ नाकाम

पूनम मसीह

बंगाल में 'खेला होबे का अब खेला शेष' हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 292 सीटों की गिनती हो गई है। दो सीटों पर 16 मई को वोटिंग होगी। बाकी की 292 सीटों में 213 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। भाजपा ने अपने पैर को और पसारते हुए 77 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं संयुक्त मोर्चा की झोली में एक भी सीट नहीं आई, एक सीट कांलिपोंग के निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती और एक सीट राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी की झोली में गई है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज 27 मार्च को हुआ और आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को डाला गया, जिसके नतीजे आने के साथ ही तीसरी बार टीएमसी ने राज्य में अपनी सरकार बना ली। साल 2011 में 34 साल बाद हुए सत्ता परिवर्तन को 10 साल बाद ही बीजेपी ने बदलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वह नाकाम साबित हुई है। बीजेपी को जितनी भी सीटें मिली हैं, वह सभी लेफ्ट और कांग्रेस की हैं। चुनाव के दौरान जब हमने आसनसोल के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीन सुमन से बात की थी, तो उन्होंने बंगाल की राजनीति पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 18 सीटें भाजपा को मिली थीं, उनमें वोट देने वाले ज्यादातर वही लोग थे जो लेफ्ट के समर्थक थे और तृणमूल से खुश नहीं थे। ऐसे वक्त में उन्हें लेफ्ट ग्रांउड पर नहीं दिखा इसलिए विकल्प के तौर पर बीजेपी को ही बेहतर समझा और वहां चले गए। इस बात को बीजेपी पहले ही समझ गई थी, इसलिए उसने बंगाल में धुव्रीवकरण करने की पूरी कोशिश पर वह नाकाम रही, क्योंकि बंगाल में लड़ाई कास्ट की नहीं क्लास की है।

नाकाम रही बीजेपी की हर चाल

पिछले साल जिस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, गृहमंत्री अमित शाह बिहार छोड़ बंगाल का दौरा कर रहे थे। एक बंगाली घर में खाना भी खाया। बांग्ला में ट्वीट किया और यहीं से बंगाल पर फतह पाने की तैयारी शुरू हो गई। यहीं आकर गृह मंत्री ने बंगाल में 200 सीट पर फतह पाने का एलान कर दिया। जिन 200 सीट के जीतने का दावा भाजपा कर रही थी, उसमें प्रदेश की 70 प्रतिशत हिंदू आबादी को ध्यान में रखते हुए कहा था। इसी 70 प्रतिशत आबादी पर भाजपा ने हिंदू-मुस्लिम धुव्रीकरण करने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की जनता ने

अपनी संस्कृति सेक्युलर छवि का परिचय देते हुए बीजेपी की 200 सीट के दावे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जिस हिंदू आबादी को भाजपा अपना कह रही थी, उसी हिंदू आबादी ने तृणमूल को 213 सीटों के साथ एक बार फिर राज्य में मजबूत बनाया है।

बंगाली बनाम गैर बंगाली का लड़ाई

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दीदी ने साफ आदेश दे दिया था कि अगर किसी को बंगाल में रहना हो तो बांग्ला बोलना ही पड़ेगा। इस बात से साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता को लेकर भी बहुत ज्यादा ही कान्शेस थीं। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप ने बताया था कि बंगाल में बंगाली अस्मिता को बरकार रखने के लिए बंगाल के हर दुकानदार को यह आदेश दिया था कि वह अपनी दुकान का नाम बांग्ला में लिखे। इतना ही नहीं अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे ट्रेड लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नैहाटी में जब ममता बनर्जी के काफिले के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया था तो दीदी ने उन्हें बाहरी करार दे दिया था, जिसको बीजेपी ने भुनाने की पूरी कोशिश की। भाजपा के बड़े नेता अपनी रैलियों के दौरान इस बात को उठाते रहे कि दीदी ने बिहार और यूपी वालों को बाहरी करार दिया है, लेकिन अगर बात करें भाषीय आधार की तो हिंदी बेल्ट की ज्यादातर सीटों पर हिंदी बेल्ट के ही उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले का आसनसोल इलाका हिंदी बेल्ट है, जहां लगभग 55 से 60 प्रतिशत हिंदी भाषीय हैं, जिसमें लगभग 15 प्रतिशत हिंदी, उर्दू बोलने वाली मुस्लिम आबादी भी है। इसके क्षेत्र में लगभग छह सीटें हैं। इसमें जामुड़िया (हरेराम सिंह) और कुल्टी (डॉ. अजय पोद्दार) विधानसभा में ही हिंदी भाषीय विजेता विधायक हैं। अन्य सीटों पर जहां भी बंगालियों की संख्या थोड़ी अच्छी है, वहां बंगाली उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, इसलिए बंगाल में लड़ाई हिंदू-मुस्लिम की नहीं बल्कि बंगाली बनाम गैर बंगाली वोटर्स की थी, क्योंकि यहां के बंगालियों को साइलेंट वोटर्स कहा जाता है। बंगाली वोटर्स जिस तरफ, जीत उस तरफ, और चुनाव के दौरान कई सर्वों में बंगालियों ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि वह बंगाल में किसी बंगाली को ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं।

बंगाल की महिला हैं ममता के साथ

प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही नंदीग्राम पर फतह नहीं पा सकीं, लेकिन राज्य में तृणमूल को जिताने में बंगाल की आधी आबादी का भी हाथ है। प्रदेश में लगभग तीन करोड़ महिला वोटर्स हैं। उन्होंने दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में अहम रोल अदा किया है। महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर वोट किया है। चुनाव के दौरान हमने कई महिलाओं से बात की। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि वह दीदी को ही अपना तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। ज्योत्सना नाम की महिला किसी के घर में काम करती हैं। वह कहती हैं कि मेरी चार बेटियां हैं मैं तो पढ़ी नहीं हूं, लेकिन दीदी ने कई तरह की सुविधा दी है। मेरी बेटी को स्कूल से साइकिल मिली है। एक को 2500 हजार रुपये मिला है। दीदी ने इतनी सारी सुविधा दी है, इसलिए वोट दीदी को ही दूंगा। कुलवंती कौर नाम की एक महिला का कहना था कि हमारे लिए गर्व की बात है कि एक महिला हमारे राज्य का प्रतिनिधत्व करती है। मैं तो चाहती हूं कि आगे भी दीदी ही हमारे राज्य की मुख्यमंत्री रहें। सुलोचना नाम की एक महिला का कहना है कि अगर दीदी न होती तो उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाती। दीदी की रूपश्री योजना के तहत 25 हजार रुपये मिले। इससे वह अपनी शादी के कई खर्चों को कर पाईं।

महिलाओं का इस तरह का समर्थन ही दीदी को एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। बंगाल की महिलाएं सजग हैं। वह हमेशा अपने मुद्दों को लेकर ही वोट करती हैं। दीदी ने अपनी घोषणा पत्र में भी महिलाओं के लिए एक स्कीम रखी है, जिसके तहत घर की मुखिया को प्रति महीना 500 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा। यही सारे मुद्दे दीदी को राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं।